

## वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण 2020-21

### अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

घरेलू वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक अड़चनों और चुनौतियों के कारण 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि कमतर रही। 2018-19 में 6.8 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 5.0 प्रतिशत रही। 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में अस्थायी गिरावट के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार मजबूत बने रहे और 2020-21 की पहली तिमाही से जीडीपी में पुनः वृद्धि होने की आशा है। राजकोषीय स्थिति समेकन मार्ग के इर्द-गिर्द बनी रही और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित लक्षित सीमाओं के भीतर रही। वैश्विक मांग लगातार धीमी रहने के बावजूद चालू खाता घाटा 2018-19 में 2.1 प्रतिशत से घटकर 2019-20 की पहली छमाही में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत पर आ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास बढ़ा जैसाकि दिसम्बर, 2019 के अंत की स्थिति के अनुसार निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बढ़ते अंतर्वाह और 457.5 बिलियन अमरीकी डालर तक अब तक सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार के संचयन से परिलक्षित होता है। 2019 में वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत का स्थान 14 स्थान ऊपर उठकर 63वें स्थान पर है। इससे, अन्य के साथ-साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास बढ़ाने में योगदान मिला है। चालू वर्ष और पिछले कुछ वर्षों में उच्च जीडीपी वृद्धि एवं महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा/कार्यान्वयन के बल पर भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।

वर्ष 2019-20 में घोषित/कार्यान्वित उपायों में 2019-20 के लिए कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि; कारपोरेट कर दर में कटौती; वस्त्र और हस्तशिल्प एवं विद्युतचालित वाहनों के विकास के लिए नीतिगत पहलें; सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का विकास तथा उनको सुसाध्य बनाने हेतु आउटरीच कार्यक्रम; भारत में स्टार्ट-अप के लिए प्रोत्साहन; वित्तीय रूप से मजबूत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की एकत्रित आस्तियों की खरीद हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एकबारगी आंशिक ऋण व गारंटी देने की योजना; सरकारी बैंकों का पुनःपूंजीकरण, किफायती (वहनीय) आवासों के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार के दिशानिर्देशों में ढील देना; ठप पड़ी आवास परियोजनाओं के लिए ₹25,000 करोड़ की रियल्टी निधि; किफायती आवास के लिए ब्याज की अतिरिक्त कर कटौती; सरकारी क्षेत्र के 10 बैंकों का चार कंपनियों में विलय; निर्यातों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के उधार देने के संशोधित मानदंड और केन्द्रीय सरकार के स्तर पर बहुत से श्रम कानूनों को दुरुस्त करना शामिल है। इसके अलावा, विनिर्माण बढ़ाने; रोजगार सृजन; वित्तीय समावेशन; डिजीटल भुगतान; मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी स्कीमों के जरिए व्यवसाय करना

आसान बनाने में सुधार जैसे अनेक कदम उठाए गए थे। सरकार ने ₹102 लाख करोड़ मूल्य की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की परियोजनाओं की भी घोषणा की है जो चरणबद्ध तरीके से 2020-21 से 2024-25 तक शुरू होगी।

### सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

वार्षिक राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2018-19 में 6.8 प्रतिशत के अनंतिम अनुमान की तुलना में वर्ष 2019-20 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 5.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके सादृश्य में, सकल मूल्य वृद्धि की वास्तविक वृद्धि वर्ष 2018-19 में 6.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 में 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 (वार्षिक अनुमान) में जीवीए वृद्धि में इस कमी का कारण लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं के सिवाय आपूर्ति के सभी क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। मांग पक्ष की तरफ से निजी अंतिम खपत व्यय, सार्वजनिक अंतिम खपत व्यय तथा निवल निर्यात से सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में गति प्रदान की है। दूसरी ओर सकल नियत पूंजी निर्माण से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कमी आई है।

### कृषि

वर्ष 2018-19 में, चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, देश में वर्ष 2017-18 की तरह ही 285 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान था। तथापि, पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन 19.2 मिलियन टन अधिक था। वर्ष 2018-19 के दौरान 116.4 मिलियन टन चावल का उत्पादन होने का अनुमान था जबकि 2017-18 में यह 112.8 मिलियन टन था। वर्ष 2018-19 के दौरान गेहूं का उत्पादन 102.2 मिलियन टन अनुमानित था जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान यह 99.9 मिलियन टन था। सरकार ने सभी अधिदेशित खरीफ, रबी तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाया है। इस बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य से 2019-20 के मौसम के लिए अखिल भारत में भारित औसत उत्पादन लागत की तुलना में 1.5 गुना प्रतिफल सुनिश्चित होता है।

भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना हुआ है। वर्ष 2018-19 में देश में दुग्ध उत्पादन 187.7 मिलियन टन था जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5 प्रतिशत अधिक है। देश में अंडा उत्पादन भी 2017-18 में 95217 मिलियन से बढ़कर 2018-19 में 103318 मिलियन हो गया है। भारत में मत्स्य उत्पादन में हालिया वर्षों में 7 प्रतिशत से अधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। देश में वर्ष 2018-19 के दौरान कुल मत्स्य उत्पादन 13.4 मिलियन टन रहा। इसमें, समुद्री मत्स्य क्षेत्र का हिस्सा 3.7 मिलियन मीट्रिक टन था और

अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र का हिस्सा 9.7 मिलियन मीट्रिक टन था। 2019-20 में 30 नवम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार कृषि ऋण के अंतर्गत 9,07,843.4 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

### कीमतें

वर्ष 2018-19 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति घटकर 3.4 प्रतिशत पर आ गई जो वर्ष 2017-18 में 3.6 प्रतिशत और 2016-17 में 4.5 प्रतिशत थी। वर्ष 2019-20 (अप्रैल से दिसम्बर) में यह औसतन 4.1 प्रतिशत रही जो दिसम्बर, 2019 में 7.3 प्रतिशत रही थी। वर्ष 2018-19 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रा स्फीति गिर कर 0.1 प्रतिशत रह गई थी जोकि वर्ष 2017-18 में 1.8 प्रतिशत और 2016-17 में 4.2 प्रतिशत थी। यह 2019-20 (अप्रैल से दिसम्बर) में औसतन 5.3 प्रतिशत थी जबकि दिसम्बर, 2019 में 14.1 प्रतिशत थी।

वर्ष 2018-19 में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुसार मापी गई मुद्रास्फीति 4.3 प्रतिशत रही जबकि वर्ष 2017-18 में 3.0 प्रतिशत तथा वर्ष 2016-17 में 1.7 प्रतिशत रही थी। वर्ष 2019-20 (अप्रैल से दिसम्बर) में यह औसतन 1.5 प्रतिशत थी जबकि दिसम्बर, 2019 में यह 2.6 प्रतिशत थी।

सरकार ने अनिवार्य खाद्य मदों की कीमतों को स्थिर रखने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापार और राजकोषीय नीतिगत साधन जैसे आयात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात प्रतिबंध, स्टॉक को सीमित करना शामिल हैं, इसके अतिरिक्त राज्यों को घरेलू उपलब्धता विनियमित करने और कीमतों को संयत रखने के लिए जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। कीमतों को संयत करने की दिशा में कृषि के प्रमुख घटकों में उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके और विभिन्न स्कीमों जैसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन और तिलहन तथा पाम तेल राष्ट्रीय मिशन आदि के कार्यान्वयन द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करती रही है। सरकार कृषि-बागवानी की वस्तुओं जैसे दालों, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को कम करने में सहायता के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) को भी लागू कर रही है।

### उद्योग

अप्रैल-नवम्बर, 2019 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 0.6 प्रतिशत बढ़ा जबकि 2018-19 में यह 3.8 प्रतिशत था। अप्रैल-नवम्बर, 2019 के दौरान आईआईपी में खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रों में क्रमशः (-) 0.1 प्रतिशत, 0.9 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 में इन तीनों क्षेत्रों में पूर्ण वार्षिक वृद्धि क्रमशः 2.9 प्रतिशत, 3.9 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत थी। अप्रैल-नवम्बर, 2019-20 में प्रयोग आधारित श्रेणियों के अंतर्गत यह वृद्धि प्राथमिक वस्तुओं में 0.1 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तुओं में (-) 11.6 प्रतिशत,

अर्धनिर्मित वस्तुओं में 12.2 प्रतिशत और अवसंरचना/विनिर्माण वस्तुओं में (-) 2.7 प्रतिशत रही। वर्ष 2018-19 में इन श्रेणियों में तत्संगत पूर्ण वार्षिक वृद्धि क्रमशः 3.5 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत, 0.9 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत थी।

आठ प्रमुख अवसंरचना सहायक उद्योगों नामतः कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में लगभग 40 प्रतिशत की कुल भागीदारी है। ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2018-19 में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2019 में स्थिर रहा। अप्रैल-नवम्बर, 2019 के दौरान उर्वरकों, इस्पात और विद्युत का उत्पादन क्रमशः 4.0 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत और 0.7 प्रतिशत रहा जबकि इसी अवधि के दौरान कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों और सीमेंट का उत्पादन क्रमशः 5.3 प्रतिशत, 5.9 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत, 1.1 प्रतिशत और 0.02 प्रतिशत घटा।

### विदेशी क्षेत्र

वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान पण्य वस्तु निर्यात (सीमा शुल्क आधारित) 239.3 बिलियन अमरीकी डालर का था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 244.1 बिलियन अमरीकी डालर पर 2.0 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान पण्य वस्तु आयात मूल्य 357.4 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि में 392.3 बिलियन अमरीकी डालर से 8.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2018-19 (अप्रैल-दिसम्बर) में तेल आयात भी 108.5 बिलियन अमरीकी डालर से गिरकर वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में 95.7 बिलियन अमरीकी डालर पर आ गए। वर्ष 2018-19 (अप्रैल-दिसम्बर) में पण्य व्यापार घाटा 148.2 बिलियन अमरीकी डालर पर था जो सुधर कर 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में 118.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

वर्ष 2018-19 में अस्थिरताओं में हुई वृद्धि के बाद, भारत के विदेशी क्षेत्र ने 2019-20 के पूर्वार्द्ध में कुछ स्थिरता हासिल की जिसमें भुगतान संतुलन (बीओपी) की अच्छी स्थिति के चलते चालू खाता घाटा वर्ष 2018-19 में 2.1 से घटकर 2019-20 के पूर्वार्द्ध में 1.5 पर आ गया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के अंतर्वाह में वृद्धि, पोर्टफोलियो में निवल बहिर्वाह से निवल अंतर्वाह के रूप में वापसी और सुदृढ़ धन विप्रेषणों की प्राप्ति हुई, इन सभी के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार में अत्यधिक वृद्धि हुई जो दिसम्बर, 2019 के अंत तक 457.5 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया।

एफडीआई के निवल अंतर्वाह में 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में वृद्धि जारी रही जिसके परिणामस्वरूप 21.2 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 24.4 बिलियन अमरीकी डालर का अर्जन हुआ, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारात्मक उपायों में बढ़ते विश्वास के प्रति वैश्विक रुझानों को प्रतिबिंबित करता है।

वर्ष 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) में रुपये की औसत मासिक विनमय दर (भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर) प्रति अमरीकी डालर 70.41 रुपये थी जबकि यही दर 2018-19 के दौरान प्रति अमरीकी डालर 69.92 रुपये थी। सितम्बर अंत 2019 की स्थिति के अनुसार विदेशी ऋण जीडीपी के 20.1 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बना रहा है। वर्ष 2014-15 से महत्वपूर्ण गिरावट देखे जाने के बाद जीडीपी की तुलना में भारत की विदेशी देनदारियां (ऋण और इक्विटी) एफडीआई, पोर्टफोलियो प्रवाहों तथा विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) में वृद्धि के कारण जून, 2019 के अंत में बढ़ गई है।

### मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता

वर्ष 2019-20 के दौरान मौद्रिक नीति समायोजनकारी बनी रही है। वित्त वर्ष 2019-20 में अब तक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की पांच बैठकें आयोजित की गई हैं। पहली चार बैठकों में, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर में कटौती करने का निर्णय लिया था। रेपो दर में 110 आधार बिंदुओं (बीपीएस) की कटौती करके इसे अप्रैल, 2019 में 6.25 प्रतिशत से घटाकर अक्तूबर, 2019 में 5.15 प्रतिशत के स्तर पर लाया गया था। दिसम्बर, 2019 में अपने पांचवें द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण में एमपीसी ने रेपो दर को 5.15 प्रतिशत स्तर पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया था।

आरक्षित निधि की वृद्धि 27 दिसम्बर, 2018 में 17.0 प्रतिशत की तुलना में 27 दिसम्बर, 2019 को 10.2 प्रतिशत के स्तर पर थी। आरक्षित निधि में बढ़ोत्तरी परिचालन मुद्रा से प्रेरित थी। स्थूल मुद्रा (एम 3) की वृद्धि में 2009 से गिरावट की प्रवृत्ति रही है। तथापि, 2018-19 से एम3 की वृद्धि में गति आई जो मुख्यतः कुल जमाराशियों में हुई वृद्धि से प्रेरित थी। एम3 की वृद्धि 20 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार 10.4 प्रतिशत थी जबकि यह 20 दिसम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार 10.2 प्रतिशत के स्तर पर थी। इस वर्ष के दौरान एम3 में अब तक हुआ विस्तार कुल जमाराशियों में हुई वृद्धि के कारण है, जिसमें 20 दिसम्बर, 2018 में 9.2 प्रतिशत की तुलना में 20 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

### बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्र

वर्ष 2019-20 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल अनर्जक अग्रिम (जीएनपीए) अनुपात मार्च, 2019 की तुलना में सितम्बर, 2019 में 9.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना हुआ है। इसी प्रकार, एससीबी का पुनर्संचित मानक अग्रिम (आरएसए) अनुपात इसी अवधि के दौरान 0.4 प्रतिशत पर बना रहा। एससीबी का भारग्रस्त अग्रिम (एसए) अनुपात भी 9.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का जीएनपीए भी सितंबर 2019 में 12.3 प्रतिशत के स्तर पर अपरिवर्तित बना रहा जबकि भारग्रस्त अग्रिम अनुपात में बढ़ोत्तरी होकर यह मार्च में 12.7 प्रतिशत के स्तर से सितंबर, 2019 में 12.9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया।

खाद्य भिन्न ऋण की वृद्धि 22 नवम्बर, 2019 को 7.2 प्रतिशत

थी जबकि यह 23 नवम्बर, 2018 को 13.8 प्रतिशत थी। ऋण में किंचित कमी वैयक्तिक ऋणों को छोड़कर खाद्य-भिन्न ऋण के सभी प्रमुख क्षेत्रों में देखी गई। वैयक्तिक ऋण में 23 नवम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार 17.2 प्रतिशत की तुलना में 22 नवम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार 16.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के पूर्वार्ध में तीव्र वृद्धि करने के पश्चात एनबीएफसी क्षेत्र में तीव्र गिरावट आयी है। एनबीएफसी से लिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि जो सितम्बर, 2018 में 31.9 प्रतिशत और दिसम्बर, 2018 में 14.6 प्रतिशत थी, वह सितंबर, 2019 के अंत में कम होकर 3.4 प्रतिशत रह गई। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के सेक्टर का तुलन-पत्र 2018-19 के दौरान 17.9 प्रतिशत बढ़कर ₹26,17,790 करोड़ से ₹30,85,480 करोड़ हो गया। एनबीएफसी के वित्तपोषण स्रोतों में दृष्टिगोचर अंतर आया है। बैंकों से उधारों में 26.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और ये अक्तूबर, 2018 में ₹5.62 लाख करोड़ से बढ़कर अक्तूबर, 2019 में ₹7.13 लाख करोड़ हो गए। तथापि, म्यूचुअल फंड द्वारा एनबीएफसी को ऋणों का परिनियोजन अक्तूबर, 2018 से संकुचित होता जा रहा है।

### पूंजी बाजार

वर्ष 2019-20 (31 दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान 85 पब्लिक और राइट्स निर्गमों के माध्यम से ₹73,896 करोड़ प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाए गए जबकि 2018-19 (31 दिसम्बर, 2018 तक) के दौरान 124 निर्गमों के माध्यम से ₹44,355 करोड़ जुटाए गए थे। वर्ष 2019-20 (31 दिसम्बर, 2019 तक) में 1,520 निर्गमों के निजी परिनियोजन के माध्यम से ₹6.29 लाख करोड़ की निधियां जुटाई गईं जबकि 2018-19 में 2006 निर्गमों के माध्यम से ₹5.3 लाख करोड़ का परिनियोजन हुआ था।

भारत के बेंचमार्क सूचकांक, नामतः निफ्टी50 तथा एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक, 2019-20 के दौरान लगातार बढ़ते रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का बेंचमार्क सूचकांक एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स 20 दिसम्बर, 2019 को अब तक के उच्चतम समापन स्तर 41,681 पर पहुंच गया, जो 1 अप्रैल, 2019 को 38,871 के स्तर में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 1 अप्रैल, 2019 की तुलना में निफ्टी50 सूचकांक ने 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और 3 जनवरी, 2020 को यह 12,226 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई और निफ्टी50 की 2019-20 (अप्रैल-दिसम्बर) की औसत वार्षिक वृद्धि क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत हुई थी।

### केन्द्रीय सरकार के वित्त

वर्ष 2019-20 के बजट में राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत एवं 2.3 प्रतिशत आकलित था। बजट अनुमान 2019-20 में कर का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 11.7 प्रतिशत और कुल व्यय का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात

13.2 प्रतिशत की परिकल्पना की गई थी। 2018-19 के संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में सकल कर राजस्व की 9.5 प्रतिशत वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। बजट अनुमान 2019-20 में कुल व्यय में 2018-19 के संशोधित अनुमान से 13.4 प्रतिशत तक वृद्धि होने की अपेक्षा थी।

अप्रैल-नवम्बर, 2019 के लिए लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी किए गए केन्द्र सरकार के वित्त से संबंधित आकड़ों के अनुसार, सकल कर राजस्व में पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि से 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो बजट अनुमान का 47.7 प्रतिशत हो गया। गैर-कर राजस्व पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में (अप्रैल-नवम्बर, 2019) के दौरान 67.8 प्रतिशत तक बढ़ गया जो बजट अनुमान का 74.3 प्रतिशत है। नवम्बर, 2019 के अंत तक, गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियां बजट अनुमान का 24.2 प्रतिशत हो गईं।

अप्रैल-नवम्बर, 2018 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 2019 के दौरान महत्वपूर्ण सस्त्रियों (खाद्य पदार्थ, पोषण आधारित उर्वरक, और यूरिया तथा पेट्रोलियम) में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-नवम्बर, 2018-19 की तुलना में 2019 के तदनुसूची अवधि के दौरान यूरिया की सस्त्रियों में 52.7 प्रतिशत और पेट्रोलियम की सस्त्रियों में 27.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अप्रैल-नवम्बर, 2019 के दौरान, राजस्व घाटा 2019-20 में बजट व्यवस्था की राशि का 114.8 प्रतिशत तक पहुँच गया। पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान, यह अनुपात 2018-19 की बजट व्यवस्था की राशि के संबंध में उसी स्तर पर बना रहा। अप्रैल-नवम्बर,

2019 का राजस्व घाटा बजट अनुमान का 128.4 प्रतिशत है और यह पिछले वर्ष में 132.6 प्रतिशत के अनुरूपी आकड़े से कम है। संशोधित अनुमान में 2019-20 में राजकोषीय और राजस्व घाटा क्रमशः जीडीपी का 3.8 प्रतिशत और जीडीपी का 2.4 प्रतिशत है।

#### संभावनाएं

अर्थव्यवस्था में वृद्धि सबसे कम प्रतीत होती है और इसका 2020-21 में बढ़ने का अनुमान है। भावी वैश्विक एवं घरेलू चुनौतियों एवं अवसरों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का आकलन करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था की भावी विदेशी बड़ी चुनौतियों में मध्य पूर्व में भौगोलिक-राजनैतिक तनाव और तेल की आपूर्ति में रुकावट के कारण कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि है जिससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि धीमी पड़ सकती है और मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। निवेश एवं बचत को पुनः प्रवर्तित करना घरेलू चुनौतियों में से एक है। संरचनात्मक सुधारों का जारी रहना अर्थव्यवस्था की सकारात्मक संभावनाओं में से एक है जिससे वृद्धि पुनः प्रवर्तित एवं नकदी प्रवाह अपेक्षित रूप से सामान्य होगा क्योंकि मौद्रिक नीति समिति द्वारा पिछली बार कार्यान्वित कारपोरेट कर दर में कटौती और रेपो रेट में कटौती के अनुमानित संप्रेषण के फलस्वरूप निवेश में वृद्धि होगी। 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होने की संभावना है और इससे भी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने में मदद मिल सकती है। आर्थिक उछाल के सकारात्मक पहलु को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में कम-से-कम 10 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है।

**वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण**  
(आर्थिक निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-दिसम्बर		प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-दिसम्बर	
		2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
<b>संपदा क्षेत्र</b>					
1.	बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ हजार करोड़) @				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	19010	20442	11.2	7.5
	(ख) वर्ष 2011-2012 के मूल्यों पर	14078	14779	6.8	5.0
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2011-12=100) @@	127.7	128.5	5.0	0.6
3.	थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	119.9	121.7	4.7	1.5
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: नई श्रृंखला (2012=100)	139.5	145.3	3.7	4.1
5.	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (₹ हजार करोड़)	14549.7	16061.6 <sup>§</sup>	10.2	10.4 <sup>§</sup>
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात*				
	(क) ₹ करोड़	2737092	2514784	23.6	-8.1
	(ख) बिलियन अमरीकी डालर	392.3	357.4	14.3	-8.9
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात*				
	(क) ₹ करोड़	1702261	1684559	18.5	-1.0
	(ख) बिलियन अमरीकी डालर	244.1	239.3	9.6	-2.0
8.	व्यापार घाटा (बिलियन अमरीकी डालर)*	-148.2	-118.1	22.9	-20.3
9.	विदेशी मुद्रा भंडार (दिसम्बर अंत तक)				
	(क) ₹ करोड़	2752310	3264729	5.1	18.6
	(ख) बिलियन अमरीकी डालर	393404	457468	-3.9	16.3
10.	चालू खाता शेष (बिलियन अमरीकी डालर)#	-34.8	-20.6		
		<b>2018-19</b>	<b>2019-20</b>	<b>2018-19</b>	<b>2019-20</b>
<b>सरकार के वित्त साधन (₹ करोड़)##</b>					
				अप्रैल से नवम्बर	
1.	राजस्व प्राप्तियां	870306	983214	8.1	13.0
	सकल कर राजस्व	1164685	1174143	7.1	0.8
	कर (केन्द्र को निवल)	731669	750614	4.6	2.6
	कर-भिन्न राजस्व	138637	232600	31.4	67.8
2.	पूंजी प्राप्तियां, जिसमें	742902	836843	10.2	12.6
	ऋणों की वसूली	10467	10910	10.5	4.2
	अन्य प्राप्तियां	15810	18099	-69.8	14.5
	उधार और अन्य देनदारियां	716625	807834	17.1	12.7
3.	कुल प्राप्तियां (1+2)	1613208	1820057	9.1	12.8
4.	कुल व्यय	1613208	1820057	9.1	12.8
	(क) राजस्व व्यय	1421778	1606215	9.8	13.0
	ब्याज भुगतान	348233	341812	12.4	-1.8
	(ख) पूंजी व्यय	191430	213842	4.0	11.7
5.	राजस्व घाटा	551472	623001	12.6	13.0
6.	प्रभावी राजस्व घाटा	416686	493783	15.3	18.5
7.	राजकोषीय घाटा	716625	807834	17.1	12.7
8.	प्राथमिक घाटा	368392	466022	21.9	26.5

@ सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के हैं और वर्ष 2018-19 के आंकड़े अंतिम अनुमान हैं और वर्ष 2019-20 के आंकड़े प्रथम अग्रिम अनुमान हैं।

@@ अप्रैल से नवम्बर तक

\* सीमाशुल्क आधार पर

§ 20 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार

# अप्रैल - सितंबर

## महालेखा नियंत्रक और वित्त मंत्रालय द्वारा यथा सूचित आंकड़े।